के स्थानान्तरण के लिए किसानों के खेत में अग्रिम एवं सामान्य प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(ग) और (घ) दलहन के मामले में, उत्पादन, जो आगे बढ़े बिना 14 मिलियन टन के आस पास रह रहा है, की अस्थिरता के लिए कई कारक जिम्मेवार हैं। तिलहन के मामले में हर वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ रिकार्ड उत्पादन करने में सफलता मिल रही है।

1990-91 के दौरान दलहन की उत्पादकता 578 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर थी जबकि 1995-96 के दौरान यह 551 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी। तिलहन के मामले में 1990-91 के दौरान उत्पादकता 771 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी और 1995-96 के दौरान 851 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी।

(ङ) 2002 ई० तक दलहन एवं तिलहनों की उत्पादकता दर में वृद्धि के लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Loss of cotton Production in Gujarat

2123. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that adverse weather conditions have affected Cotton production in Gujarat, particularly in the Saurashtra region, during 1996-97 season and Cotton growers have incurred heavy losses there from:

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government to mitigate the sufferings of Cotton growers of Gujarat, with details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) There has been no adverse weather conditions in Gujarat State. The produciton of Cotton in the state in fact is expected to be 28 lakh bales during 1996-97 which is 6 lakh bales higher than that during 1995-96.

(c) As a result of increased production/ supply, the prices of Cotton in Gujarat have declined in the current year, compares with last year, but these are ruling well above the minimum support levels. The State Government has asked the Gujarat State Cooperative Federation Ltd. (GUJCOT) to step up purchase of cotton from the farmers and has undertaken to bear losses, if necessary. The GUJCOT has so far purchased 1.33 lakh bales of cotton amounting to Rs. 129.50 crore.

The government of India has been taking various steps to help cotton growers:

(i) The minimum support prices (MSP) of various varieties were announced before the start of the season.

(ii) Export quota of 12.20 lakh bales of cotton has been released during the current year of which one lakh bales of cotton is alloted to GUJCOT. In addition spill-over quantity of 6.90 lakh bales (approx). from the export quota of 1995-96 season has been permitted to be exported by 28.2.97.

(iii) The Cotton Corporation of India (CCI) has been making aggressive purchases to give support to cotton growers. As on 23.2.97 the CCI purchases during the current season have been 7.81 lakh bales as compared to 6.14 lakh bales as on the corresponding date in the previous year. The CCI and GUJCOT have purchased 3.55 lakh bales and exported 1.69 lakh bales of cotton from Gujarat during the current season. State marketing Federation and NAFED have also given export quotas and have also been buying cotton.

(iv) The ceiling of export of cotton yarn of counts below 41s in 1996 was increased from 80 million kgs. to 110 million kgs. For the year 1997, the ceiling for export of cotton yarn below counts 41s has been further enhanced to 120 million kgs.

(v) Cotton has been removed from Selective Credit Control.

(vi) There are no on stock-limits for cotton.

(vii) In the Central Budge proposals for 1997-98, it has been proposed to repeal Ginning and Pressing Factories Act of 1925 and the Cotton Control

Order of 1986 will be invoked only in well defined emergency situation. Domestic futures trading would be resumed in respect of ginned and baled cotton.

डेयरी उद्योग की स्थापना हेतु प्रोत्साहन

2124. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डेयरी उद्योग की स्थापना हेतु कोई प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिपुरा सहित पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी उद्योग की स्थापना हेतु आवेदकों को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र को योजना स्कीम की एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत सहकारी समितियों को डेयरी विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। विभिन्न राज्यों को 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नीचे देखिए

(ग) और (घ) कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं। जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, 1993-94 तथा 1994-95 में राज्य के लिए 625 लाख रुपये के कुल निवेश के साथ दो परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी जिसमें सभी जिले शमिल हैं।

विवरण

गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम के अंतर्गत 1993-94, 1994-1995 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का विवरण।

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदन वर्ष	1993-94 में जारी की गई राशि	1994-95 में जारी की गई राशि	1995-96 में जारी की गई राशि
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1995-96	0.00	0.00	91.00
2.	आंध्र प्रदेश	1995-96	0.00	0.00	250.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	1993-94	100.00	150.00	0.00
4.	असम	1994-95	0.00	400.00	0.00
5.	बिहार-1	1994-95	0.00	75.00	0.00
	बिहार-2	1995-96	0.00	0.00	150.00
6.	गुजरात	1993-94	150.00	0.00	150.00
7.	हरियाणा	1995-96	0.00	0.00	15.00
8.	जम्मू व कश्मीर-जम्मू	1995-96	0.00	0.00	75.00
9.	मध्य प्रदेश-1,2 व 3	1993-94	225.00	290.00	150.00
	मध्य प्रदेश-4	1995-96	0.00	0.00	163.00
10.	महाराष्ट्र	1995-96	0.00	0.00	200.00
11.	मणिपुर	1993-94	25.00	100.00	0.00
12.	मेघालय	1994-95	0.00	75.00	0.00